Government is implementing the Integrated Cereals and Development Programme in Rice Based Cropping System Areas and National Pulses Development Project which are to continue during the 9th Five Year Plan. The increase in area under cereals and pulses through these programmes is envisaged only through intensive use of land in various seasons.

सिंचित तथा असिंचित भूमि की उपज दर

908.**श्री बजजिन्दर सिंह**:

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचित तथा असिंचित भूमि की उपज दर में भारी अन्तर हैं;

(ख) यदि हां,तो सिंचित तथा असिंचित भूमि की उपज दर के संबंध में सरकार का क्या अनुमान हैं; और

(ग) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कुल कृषि उत्पादन की तुलना में सिंचित और असिंचित भूमि से कितने-कितने प्रतिशत उपज के होने का अनुमान हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सोप पाल): (क) से (ग) जी हां,देश में सिंचित और असिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत,विभिन्न फसलों की उपज की दरों में अन्तर रहता है । तथापि,इस संबंध में सभी राज्यों/फसलों के बारे में सरकारी अनुमान क्रमबद्व रूप में उपलब्ध नहीं है जिससे इन अनुमानों को अखिल भारतीय स्तर पर परिणाम निकाला जा सके ।

Strike Threat by Fishermen

909. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the fishermen all over the country threatened to go on agitation including strike;

(b) if-so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to find a solution to the threatened strike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No intimation of agitation/strike from fishermen all over the country have been received.

(b) and (c) The question do not arise.

Suicide by Farmers

910. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the large number of suicides committed by farmers in different States;

(b) if so, the States from where such incidents have came to the notice of Government;

(c) the reasons why the farmers in those States have committed suicides; and

(d) the Steps taken to help the fanners in those States which are facing same kind of problems?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) The State Government of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have reported total such suicidal deaths as 236, 29 and 51, respectively, mainly as a result of damage to crops due to natural calamities.

It is primarily the responsibility of the State Governments conerned T provide relief to the people affected by natural calamities from their annual allocation under the Calamity Relief Fund (CRF). Additional assistance, if any, is provided from the National Fund for Calamity Relief (NFCR) in the event of calamities of rare severity. An additonal assistance of Rs. 12.00 crore was released to the Government of Andhra Pradesh during 1997-98, from the NFCR in the wake of damage to crops, mainly cotton, due to pest attack. The Government of Andhra Pradesh has sanctioned ex-gratia of Rs. 1.00 lakh to the next of kin of each deceased while the Government of Karnataka has sanctioned ex-gratia of Rs. 1.00 lakhs each in 13 suicidal cases which has some relation to crop loss and the

Government of Maharashtra has paid Rs. 1.00 lakh per family in 12 suicide cases having direct linkage with crop loss/indebtedness and Rs. 30,000/- per family in 7 cases having some linkage with crop loss. In addition, the Government of Andhra Pradesh has announced several package measures of relief to the affected farming families and the Government of Karnataka has released Rs. 4.00 crores as one-time assistance in the form of input subsidy to the affected small and marginal farmers.

पशुधन में कमी

911.**श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में पशुधन की संख्या कितनी थी और इस समय यह कितनी है;

(ख) देश में पशुधन में हो रही लगातार कमी के प्रमुख कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कृषि कार्यो में पशुधन के महत्व का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) पशुधन में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस उपाय किये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) पशुधन संख्या 5 साल में एक बार आयोजित पशुधन गणना के आधार पर तय की जाती है । पशुधन गणना 1951 के अनुसार कुल पशुधन संख्या 292.80 मिलियन थी और पशुधन गणना 1992 के अनुसार यह संख्या 470.14 मिलियन थी । 1997 की गणना से संबंधित काम चल रहा है ।

(ख) देश में पशुधन में कोई गिरावट नहीं आई हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के राष्ट्रीय लेखों के 1996-97 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र से 3570 बिलियन रूपए के कुल उत्पादन की तुलना में पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का कुल मुल्य 897 बिलियन रूपए रहा है जो कृषि क्षेत्र के कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हैं ।

(ड़) (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कुकुट विकास बोर्ड का गठन

912.**श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कुकुट विकास बोर्ड का गठन का निर्णय लिया था,यदि हां,तो इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्त वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के लिए राष्ट्रीय कुकुट विकास बोर्ड को किसी धनराशि का आबंटन किया था; यदि हां,तो उसके उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है;और

(ग) क्या पांच वर्षो तक बजट आबंटन के अनुपयोग के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया था;यदि हां,तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री सोमपाल): (क) जी,नहीं ।

(ख) वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के दौरान राष्ट्रीय कुकुट विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए निम्नांकित राशि उपलब्ध कराई गई थी

	करोड़ रू.में
1992-93	0.20
1993-94	3.50
1994-95	4.00
1995-96	2.60
1996-97	2.60

बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव की जांच पड़ताल,करने के बाद योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया था कि इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई न की जाए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्न उत्पादन

913.**श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवी पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक दर निर्धारित की गयी है;